राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • सोमवार • 5 फरवरी • 2024
www.rashtriyasahara.com

आडवाणी को सर्वोच्च सम्मान

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी (96) को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि भारत के विकास में आडवाणी का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना निश्चित ही स्वागतयोग्य है। आडवाणी ने भी उन्हें भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि यह न केवल उनका, बल्कि उनके आदर्शों और सिद्धांतों का भी सम्मान है। आडवाणी को नब्बे के दशक में भाजपा के उदय का श्रेय दिया जाता है। आडवाणी भाजपा के संस्थापकों में शुमार हैं। हालांकि राजनीति में आडवाणी भारतीय जनसंघ से होते हुए आए और उससे पहले, आजादी से भी काफी पहले, 1941 में चौदह साल की आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ चुके थे। संघ ने राजनीति प्लेटफॉर्म के रूप में जब 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की तो आडवाणी उससे जुड़ गए थे। आपातकाल के बाद जनसंघ के साथ ही समाजवादियों, चौ. चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम ने जनता पार्टी का गठन किया तो जनसंघ उसकी घटक बनी और बाद का घटनाक्रम ऐसा रहा जिसके चलते जनसंघ को जनता पार्टी से अलग होना पड़ा। बाद में यह भारतीय जनता पार्टी के रूप में भारत के राजनीतिक पटल पर उभरी। इसके प्रमुख संस्थापकों में लालकृष्ण आडवाणी भी थे। 25 सितम्बर, 1990 में उन्होंने अयोध्या में राममन्दिर की भाजपा की मांग को लेकर रथयात्रा आरंभ की जो गुजरात के सोमनाथ से आरंभ होकर अयोध्या पहुंची। देश भर इसे भारी जनसमर्थन मिला। भाजपा इसी मांग को लेकर सक्रिय हुई तो उसने देश की राजनीति की दिशा-दशा बदल डाली। आज यह पार्टी देश में मजबूती से सत्ता पर काबिज है, और प्रधानमंत्री पद पर आसीन नरेन्द्र मोदी तीसरी बार भाजपा को सत्ता में लौटाने का दावा कर रहे हैं। कहना होगा कि भाजपा के शिल्पकार के रूप में आडवाणी ने जो स्वप्न देखा वह आज राम मन्दिर के रूप में साकार हो चुका है और इसके स्थापना वर्ष में ही देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से आडवाणी को नवाजा जा रहा है। राजनीति में शुचिता के पैरोकार आडवाणी ने अपने दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई है, राजनीतिक नैतिकता का अनुकरणीय मानक स्थापित किया। यकीनन वे इस सम्मान के हकदार हैं।

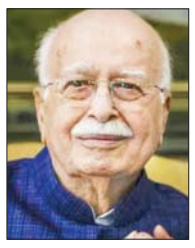

मौत पर मसखरी

यह मौत का मजाक था या मसखरी में किया गया मौत का ढोंग। जागरूकता के नाम पर पूनम पांडे ने जो स्वांग किया, उस पर लोग अवाक हैं। सर्वाइकल कैंसर के कारण पूनम की मौत की खबर ने लोगों को चौंका दिया। अगले दिन पांडे ने वीडियो पोस्ट किया-'मैं यहां हूं, और जीवित हूं।' उसने अपनी मौत की झूठी खबर के लिए माफी मांगी और कहा कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में अहम जानकारी प्रसारित करना चाहती थी। 'मैं जानती हूं आपको बुरा लगा होगा, लेकिन इस बीमारी पर विचार का अनुरोध करती हूं।' जिस रोज पांडे की मौत की खबर आई उससे एक दिन पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट की घोषणा की थी जिसमें सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9-14 वर्ष की बच्चियों के टीकाकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। बत्तीस साल की यह सोशल मीडिया स्टार अपने कामुक वीडियोज के लिए प्रसिद्ध है जिस पर अश्लीलता फैलाने का भी आरोप लगता रहा है। दस साल पहले विश्व कप क्रिकेट के दौरान इसने यह कह कर सनसनी फैला दी थी कि भारत विजेता रहा तो वह अपने कपड़े उतार देगी। कुछ फिल्में व टीवी रियलिटी शो करने के साथ वह विवादित बयानों के लिए भी जानी जाती है। मौत की खबर पर लोगों ने अंदेशा जाहिर किया था कि यह उसकी कोई चाल होगी या सिर्फ चर्चा में आने के लिए झूठ फैलाया गया है। सच यह है कि सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय की ग्रीवा में होने वाले इस संक्रमण से प्रति वर्ष हजारों महिलाएं जान से हाथ धोती हैं। अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ग्लोबोकैन के अनुसार 1,23,907 नये सर्वाइकल कैंसर के मामले भारत में 2020 में सामने आए जबकि साल भर में 77,348 मौतें हुईं। इसे स्तन कैंसर के बाद दूसरा सबसे खतरनाक कैंसर माना जाता है, जो जागरूकता की कमी के कारण महिलाओं को चपेट में ले लेता है। बावजूद इसके जिस तरह पांडे ने जागरूकता के नाम पर मसखरी की वह उचित नहीं कही जा सकती। हालांकि अपने यहां कौव्वा सिर पर बैठने पर भी लोग अपनी मौत की खबर प्रचारित करते रहे हैं। मगर वे अज्ञानी और भोले लोग थे। अपने मुरीदों की भावनाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ सतही हरकत ज्यादा कही जाएगी क्योंकि ढेरों तरीके हैं, जिनसे महिलाओं में सेहत के प्रति जागरूकता फैलाई जा सकती है।

परिधि/ राजीव मंडल

बच्चों में न देखें सपने

राजस्थान का कोटा फिर से चर्चा में है। वैसे भी अब यह कोचिंग हब के रूप में कम सुसाइड क्षेत्र के तौर पर ज्यादा कुख्यात हो चला है। 2024 का अभी पहला महीना ही समाप्त हुआ है, मगर 3 विद्यार्थियों ने अपनी जीवन-लीला खत्म कर ली। पिछले वर्ष यहां 25 से ज्यादा बच्चों ने खुदकुशी की थी। तब यह निर्णय लिया गया था कि बालकनियों और लॉबी में जाल लगाए जाएंगे। साथ ही, हॉस्टल में पंखे एंटी-सुसाइड से युक्त होंगे।

बहरहाल, जो मसला सबसे ज्यादा गंभीर, विचारणीय और प्रासंगिक है; उस पर या तो किसी की नजर नहीं है, या प्रशासन उन महत्त्वपूर्ण बिंदुओं की अनदेखी कर रहा है। हमने ज्यादातर खुदकुशी के मामलों में पाया है कि बच्चे परिजनों के दबाव में आकर न केवल अपने कॅरियर बल्कि जान भी गंवा रहे हैं। ठीक है कि प्रशासन ने खुदकुशी करने के उन रास्तों पर पहरा लगाया है, या उसे बेअसर करने के उपाय अमल में ला रही है, किंतु असल मर्ज की दवा तलाशने की जरूरत है। रैंकिंग में अव्वल आने और तमाम कोचिंग सेंटरों से बेहतर करने के लालच में ये कोचिंग केंद्र 'हत्यारे' बन रहे हैं। सही मायने में तो कोचिंग केंद्रों के सिस्टम में एंटी सुसाइड डिवाइस लगाने की जरूरत है। सिर्फ एंटी सुसाइड डिवाइस न लगाने वाले कोचिंग को सील करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। प्रशासन और सरकार को असली बीमारी की सर्जरी करने की जरूरत है।

हां, राज्य सरकार की ओर से कोटा में छात्रावासों के वार्डन और स्टाफ सदस्यों को मेस प्रबंधन, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक परामर्श और छात्रों की देखभाल के अन्य पहलुओं में पेशेवर प्रशिक्षण देने का फैसला जरूर दूरगामी असर डालेगा और इससे छात्रों और उनके अभिभावकों को चिंता के भंवर से निकलने में मदद मिलेगी। बहरहाल, मेरा सीधा सवाल यही है कि उन मां-बाप को इस बात की सीख कौन देगा कि बच्चों को डॉक्टर-इंजीनियर बनाना ही जिंदगी में सब कुछ पाना नहीं है। इससे परे भी दुनिया है। बच्चों की इच्छा का सम्मान करना हर मां-बाप का फर्ज है। मगर यह भी सोचना होगा कि बच्चे के मन में क्या है, उसकी रुचि किस ओर है? यह सब जानना दुष्कर नहीं है बशर्ते परिजन बच्चों को दोस्त की तरह समझें। बच्चों पर अपनी मनमर्जी थोपना इस गूढ़ समस्या का हल तो कतई नहीं है।

अनमोल वचन

जो प्रेम अपने को नित्य नवीन नहीं रखता, वह पहले आदत का रूप धारण कर लेता है, और फिर दासता में परिवर्तित हो जाता है।
-खलील जिब्रान

संपादकीय 4

editpagesahara@gmail.com

सफलता पर संशय

'इडिया' अलायंस

विनीत नारायण

देश के मौजूदा राजनैतिक माहौल में दो खेमे बंटे हैं। एक तरफ वो करोड़ों लोग हैं, जो दिलोजान से नरेन्द्र मोदी को चाहते हैं, और यह मानकर बैठे हैं, 'अब की बार चार सौ पार।' इनके इस विश्वास का आधार है मोदी की आक्रामक कार्यशैली, श्रीराम लला की प्राण-प्रतिष्ठा, मोदी का बेहिचक होकर हिन्दुत्व का समर्थन करना, काशी, उज्जैन, केदारनाथ, अयोध्या, मिर्जापुर और अब मथुरा आदि तीर्थ स्थलों पर भव्य कॉरिडोरों का निर्माण, अप्रवासी भारतीयों का भारतीय दूतावासों में मिल रहा स्वागतपूर्ण रवैया, निर्धन वर्ग के करोड़ों लोगों को उनके बैंक खातों में सीधे पैसा ट्रांसफर होना, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बंटना और भविष्य के आर्थिक विकास के बड़े-बड़े दावे।

दूसरे खेमे के नेताओं और उनके करोड़ों चाहने वालों का मानना है कि देश के युवाओं में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि दो करोड़ रोजगार हर वर्ष देने का वायदा करके भाजपा की मोदी सरकार देश के नौजवानों को सेना, पुलिस, रेल, शिक्षा और अन्य सरकारी विभागों में नौकरी देने में नाकाम रही है। आज भारत में बेरोजगारी की दर पिछले 40 वर्षों में सबसे ज्यादा है जबकि मोदी के वायदे के अनुसार इन दस वर्षों में 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाती तो किसी को भी मुफ्त राशन बांटने की नौबत ही नहीं आती क्योंकि रोजगार पाने वाला हर युवा अपने परिवार के पांच सदस्यों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी उठा लेता यानी देश के 100 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर उठ जाते। इसलिए इस खेमे के लोगों का मानना है कि इन करोड़ों युवाओं का आक्रोश भाजपा को तीसरी बार केंद्र में सरकार नहीं बनाने देगा। विपक्ष के इस खेमे के अन्य आरोप हैं कि भाजपा सरकार महंगाई को काबू नहीं कर पाई। उसका शिक्षा और स्वास्थ्य बजट लगातार गिरता रहा है जिसके चलते आज गरीब आदमी के लिए मुफ्त या सस्ता इलाज और सस्ती शिक्षा प्राप्त करना असंभव हो गया है।

इसी खेमे का यह भी दावा है कि मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में विदेशी कर्ज की मात्रा 2014 के बाद कई गुना बढ़ा दी है। इसलिए बजट में से भारी रकम केवल ब्याज देने में खर्च हो जाती है, और विकास योजनाओं के लिए मुट्ठी भर धन ही बच रहता है। इसका खमियाजा देश की जनता को रोज बढ़ती महंगाई और भारी टैक्स देकर झेलना पड़ता है। इसलिए सेवानिवृत्त लोग, मध्यम वर्ग और व्यापारी परेशान हैं। इसके अलावा, विपक्षी दलों के नेता मोदी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों और चुनाव आयोग के लगातार दुरुपयोग का आरोप भी लगाते रहे हैं।

इसी विचारधारा के कुछ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता ईवीएम के दुरुपयोग का आरोप लगा कर आंदोलन चला रहे हैं। दूसरी तरफ, इतने लंबे चले किसान आंदोलन की समाप्ति पर जो आश्वासन दिए गए थे, वो आज तक पूरे नहीं हुए। इसलिए इस खेमे का मानना है कि देश का किसान अपनी फसल के वाजिब दाम न मिलने के कारण मोदी सरकार से खफा है। इसलिए इनका विश्वास है कि किसान भाजपा को तीसरी बार केंद्र में सत्ता नहीं लेने देगा। अगर विपक्ष के दल और उनके नेता पिछले साल भर में उपरोक्त सभी सवालों को दमदारी से जनता के बीच जाकर उठाते तो वास्तव में मोदी के सामने 2024 का चुनाव जीतना भारी पड़ जाता। इसी उम्मीद में पिछले वर्ष सभी प्रमुख दलों ने मिलकर 'इंडिया' अलायंस बनाया था पर उसके बाद न तो इस अलायंस के सदस्य दलों ने एक साथ बैठकर देश के विकास के मॉडल पर कोई दृष्टि साफ की, न कोई साझा एजेंडा तैयार किया, जिसमें बताया जाता कि ये दल अगर सत्ता में आ गए तो बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से कैसे निपटेंगे। उन्होंने अपना कोई एक नेता भी नहीं चुना है। हालांकि लोकतंत्र में इस तरह के संयुक्त मोर्चे को चुनाव से पहले अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार तय करने की बाध्यता नहीं होती।

चुनाव परिणाम आने के बाद ही प्रायः सबसे ज्यादा सांसद लाने वाले दल का नेता प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है पर भाजपा इस मुद्दे पर अपने मतदाताओं को समझाने में सफल रही है कि विपक्ष के पास मोदी जैसा कोई सशक्त नेता प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। यह भी बार-बार कहा जाता है कि 'इंडिया' अलायंस के घटक दलों का हर नेता प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है। 'इंडिया' अलायंस के घटक दलों ने इतना भी अनुशासन नहीं रखा कि वे दूसरे दलों पर नकारात्मक बयानबाजी न करें जिसका गलत संदेश गया। 'इंडिया' अलायंस के बनते ही सीटों के बंटवारे का काम हो जाना चाहिए था जिससे उम्मीदवारों को अपने-अपने क्षेत्र में जनसंपर्क करने के लिए काफी समय मिल जाता पर शायद इन दलों के नेता ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग की धमकियों से डर कर पूरी हिम्मत से एकजुट नहीं रह पाए। यहां तक कि क्षेत्रीय दल भी अपने कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर प्रचार करने का काम आज तक शुरू नहीं करा पाए हैं। इसलिए यह अलायंस बनने से पहले ही बिखर गया। दूसरी तरफ, भाजपा और आरएसएस ने हमेशा की तरह चुनाव को युद्ध की तरह लड़ने की रणनीति 2019 का चुनाव जीतने के बाद से ही बना ली थी और आज वो विपक्षी दलों के मुकाबले बहुत मजबूत स्थिति में खड़े हैं। उसके कार्यकर्ता घर-घर जा रहे हैं, जिनसे अलायंस के घटक दलों को इनसे पार पाना लोहे के चने चबाना जैसा होगा। साथ ही, पिछले नौ वर्षों में भाजपा दुनिया की सबसे धनी पार्टी हो गई है। इसलिए उससे पैसे के मामले में मुकाबला करना आसान नहीं होगा।

आज देश के मीडिया की हालत तो सब जानते हैं। प्रिंट और टीवी मीडिया इकतरफा होकर रात-दिन केवल भाजपा का प्रचार करते हैं जबकि विपक्षी दलों को इन मीडिया में जगह ही नहीं मिलती। जाहिर है कि चौबीस घंटे एकतरफा प्रचार देखकर आम मतदाता पर तो प्रभाव पड़ता ही है। इसलिए नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा बार-बार आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, 'अब की बार चार सौ पार।' जबकि विपक्ष के नेता मानते हैं कि भाजपा को उनके दल नहीं, बल्कि 1977 और 2004 के चुनावों की तरह आम मतदाता ही हराएगा। भविष्य में क्या होगा यह तो चुनावों के परिणाम आने पर ही पता चलेगा? 'इंडिया' अलायंस के घटक दलों ने बाजी क्यों हारी? और अगर जीती तो किन कारणों से जीती?

देश के मीडिया पर चौबीस घंटे एकतरफा प्रचार देखकर मतदाता पर तो प्रभाव पड़ता ही है। इसलिए मोदी, शाह, नड्डा आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, 'अब की बार चार सौ पार।' जबकि विपक्ष मानता है कि भाजपा को उनके दल नहीं, बल्कि 1977 और 2004 के चुनावों की तरह आम मतदाता ही हराएगा। भविष्य में क्या होगा? यह तो चुनाव परिणाम आने पर ही पता चलेगा कि 'इंडिया' अलायंस ने बाजी हारी या जीती? जीती तो किन कारणों से जीती

भारत में सोने की मांग में 3 फीसद तक गिरावट

- भारत में सोने की मांग 2023 में सालाना आधार पर 3 फीसद की गिरावट के साथ 747.5 टन रही। विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) की रिपोर्ट 'सोने की मांग का रुझान' में यह जानकारी दी गई है
- रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में देश में सोने की कुल मांग 774.1 टन थी। डब्ल्यूजीसी के क्षेत्रीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी (भारत) सोमसुंदरम पी. आर. के मुताबिक, सोने की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से मांग प्रभावित हुई

(स्रोत : डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट)

आज के सोशल मीडिया के दौर में जब विभिन्न समाज में शब्दों के भिन्न अर्थ हैं, और हर किसी को हर कोई कह-सुन रहा है, तो समूचा विश्व भ्रम में है, पहले ऐसा कभी-कभार होता था जब दक्षिण भारत में उत्तर भारत के लिए 'नकार' था।

कौशिक बसु, अर्थशास्त्री
@kaushikcbasu

स्थिति में सुधार की बड़ी गुंजाइश

स्कूल फीस

सुशील देव

निजी स्कूलों में बच्चों का नामांकन करवाना जितना चुनौती भरा काम है, उससे कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है उनकी फीस भरना। पटना हाई कोर्ट ने वैसे माता-पिताओं की दुखती रग पर हाथ रखते हुए जो फैसला दिया है, वह राहत पहुंचाने वाला है। दरअसल, पटना हाई कोर्ट ने अपने फैसले में निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने वाले कानून को संवैधानिक करार दिया है यानी फीस बढ़ाने को लेकर अब कोई भी निजी स्कूल मनमानी नहीं कर सकता।

इस फैसले का दूरगामी असर अन्य राज्यों पर भी पड़ सकता है। मनमानी फीस बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने वाला हाई कोर्ट का यह फैसला भले बिहार के लिए आया हो लेकिन इससे हर राज्य के त्रस्त माता-पिता या अभिभावक खुश होंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर लगी रोक हटा थी, जिसमें निजी स्कूलों को कोरोना काल यानी 2020-21 सत्र के दौरान ली गई स्कूल फीस का 15 फीसद समायोजित या भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। तब यह रोक केवल उन तीन स्कूलों के पक्ष में लागू हुई थी, जिन्होंने अपने खातों और बैलेंस शीट का हलफनामा दायर नहीं किया था। तब पिछले पांच सालों के खर्च का ब्यौरा समेत बैलेंस शीट तलब के साथ ही राज्य प्रशासन को छह सप्ताह तक इन स्कूलों के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करने का भी निर्देश दिया गया था। स्कूल चाहे सरकारी या निजी भूमि पर बना हो, राजधानी दिल्ली में किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने में मनमानी की इजाजत नहीं है। वहीं दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की मनमानी रोकने के लिए शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के बैंक खाते जांचने की तैयारी भी की थी, जिसमें सरकारी या निजी भूमि पर बने स्कूलों के बैंक खातों का तीन साल का लेखा-जोखा जांचा गया। इस बाबत कुछ कार्यवाही किए जाने की भी सूचना है।

वहीं, हाल में दिल्ली सरकार ने 101 निजी स्कूलों के जमीन आवंटन को रद्द करने की डीडीए से सिफारिश की है। आठ स्कूलों की लीज खत्म कर भी दी गई है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने हाई कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा है कि ये स्कूल नियमों की अवहेलना कर रहे थे और ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आरक्षित 25 फीसद सीटों

के नियम को दरकिनार कर रहे थे। दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स का नियम 17-3 कहता है कि किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने के लिए प्रबंध समिति में प्रस्ताव पारित करना होगा और शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी। विभाग को अगर लगता है कि फीस बेवजह बढ़ाई जा रही है तो वह रोक लगा सकता है। कुछ स्कूल मालिकों की दलील है कि समय के साथ फीस बढ़ाना होता है। शिक्षकों को सैलरी देनी होती है। स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्गों के लिए 25 प्रतिशत सीटें देनी होती हैं। इस पैसे को सरकार समय से वापस भी नहीं करती। वार्षिक या डवलपमेंटल फीस के मामले को लेकर अभी नीति स्पष्ट नहीं है।

शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि भारत में अच्छे या नामचीन स्कूलों की ट्यूशन फीस सालाना 1 से 2 लाख रुपये तक भी है जबकि स्कूल की एडमिशन फीस के नाम पर 25 हजार से 1 लाख रुपये तक देना पड़ता है। असल में, निजी स्कूलों में बेहतर बुनियादी ढांचा और सुविधाएं होती हैं, जो छात्रों के समग्र विकास में मदद करती हैं। ठीक इसके उलट वे ऐसी फीस की मांग करते हैं, जो बहुत अधिक होती है और माता-पिता के लिए वहन करने योग्य नहीं होती। निजीकरण और महंगी शिक्षा के कारण देश में निजी स्कूल महंगे हो रहे हैं। वजह यह भी है कि सरकारी स्कूल का संचालन सरकार के हाथ में तथा निजी स्कूलों का संचालन निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। सरकारी स्कूल का भवन छोटा और अनाकर्षक होता है जबकि निजी स्कूलों का भवन बड़ा और आकर्षक होता है। ऐसे में निजी स्कूल बिना कोई सेवा प्रदान किए फीस बढ़ाने की मांग करता है, तो इसे मुनाफाखोरी और शिक्षा का व्यावसायीकरण ही कहा जाएगा।

सनद रहे कि पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए 2019 में बनाए गए कानून को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कर दी थी। मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव राय की खंडपीठ ने 'एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल, बिहार' नामक संस्था की रिट याचिका खारिज करते हुए बिहार प्राइवेट स्कूल फीस नियमितीकरण अधिनियम, 2019 को संवैधानिक और कानूनी तौर पर सही ठहराया। अच्छी बात यह है कि खंडपीठ ने आदेश दिया है कि हर प्रमंडलीय स्तर पर गठित होने वाली फीस रेग्युलेशन कमेटी में दो सदस्यों का चुनाव छात्रों के माता-पिता या अभिभावक के बीच से होना चाहिए। ऐसे में फीस को लेकर सुधार की बड़ी गुंजाइश दिखाई देती है।

अभ्यास

श्रीराम शर्मा आचार्य

सतत अभ्यास द्वारा शरीर एवं मन को इच्छानुवर्ती बनाया जा सकता है तथा उन्हें असामान्य कार्यों को कर सकने के लिए भी सहमत किया जा सकता है। मानव शरीर अनगढ़ है और वृत्तियां असंयमित। इन्हें सुगढ़ एवं सुसंयमित करना ही अभ्यास का लक्ष्य है। अभ्यास से ही आदतें बनती हैं, और अंततः संस्कार का रूप लेती हैं। परोक्ष रूप से

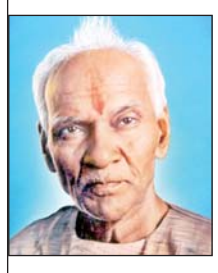

अभ्यास की यह प्रक्रिया ही व्यक्तित्व का निर्माण करती है। कितने ही व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में अपने को असमर्थ मानते हैं। उन्हें असंभव जान कर प्रयास नहीं करते। फलस्वरूप कुछ विशेष कार्य नहीं कर पाते, अपनी मान्यताओं के अनुरूप हेय एवं असमर्थ ही बने रहते हैं जबकि किसी भी कार्य को करने का संकल्प कर लेने एवं आत्मविश्वास जुटा लेने वाले व्यक्ति उसमें अवश्य सफल होते हैं। मानवीय काया परमात्मा की विलक्षण संरचना है। सर्वसमर्थता के बीज उसके अंदर विद्यमान हैं। उसे जैसा चाहे ढलाया, बनाया जा सकता है। सामान्यतया लोग कुछ दिनों तक तो बड़े उत्साह के साथ किसी भी कार्य को करने का प्रयास करते हैं, पर अभीष्ट सफलता तुरंत न मिलने पर प्रयत्न छोड़ देते हैं। फलस्वरूप अपने प्रयत्नों में असफल सिद्ध होते हैं जबकि धैर्य एवं मनोयोगपूर्वक सतत अभ्यास में लगे व्यक्ति असामान्य क्षमताएं तक विकसित कर लेते हैं। अभ्यास आदतों का रूप लेने पर चमत्कारी परिणाम प्रस्तुत करते हैं। अभ्यास की प्रक्रिया द्वारा शारीरिक-मानसिक क्षमताओं का विकास ही नहीं, रोगों का निवारण भी किया जा सकता है। शरीर एवं मनोभावों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर व्यक्ति स्वयं को उपयोगी अभ्यासों के लिए सहमत करता है। मानवीय काया एवं मन में विकास की असीम संभावनाएं हैं। निर्धारित लक्ष्य की ओर प्रयास चल पड़े और उसमें धैर्य एवं क्रमबद्धता का समावेश हो जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। पहलवान, विचारवान, कवि, लेखक, वक्ता, चित्रकार, वैज्ञानिक, अध्यापक कोई अकस्मात नहीं बन जाते, वरन उन्हें उसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है। शरीर एवं मन को निर्धारित लक्ष्य के लिए अभ्यस्त करना होता है। प्रयत्न करने पर कोई भी व्यक्ति अपने अनगढ़ शरीर एवं मन को प्रशिक्षित कर सकता है। अनगढ़ शरीर एवं मन को सुगढ़ एवं व्यवस्थित करने के लिए पूरे धैर्य के साथ सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है।

रीडर्स मेल

आडवाणी को सम्मान का स्वागत

भाजपा को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में लालकृष्ण आडवाणी का अतुलनीय योगदान रहा। भाजपा को पहली बार सत्ता में लाने का श्रेय आडवाणी और वाजपेयी की जोड़ी को जाता है, जिस भाजपा ने पहली बार गैर-कांग्रेस सरकार का कार्यकाल पूरा किया। आडवाणी ने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में उच्च आदर्श, नैतिकता एवं ईमानदारी को स्थान दिया। उन्होंने राममन्दिर के निर्माण के लिए देश में रथयात्रा निकाली थी। उनकी रथयात्रा ने इस मुद्दे को जन-जन का मुद्दा बना दिया एवं देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नींव रखी। आडवाणी ने अपने राजनीतिक जीवन में परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने सदैव योग्य युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने का कार्य किया। अयोध्या में राममन्दिर के निर्माण के पश्चात आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करना स्वागतयोग्य है।

हिमांशु शेखर, गया, बिहार

विकास गुणवत्तापूर्ण हो

2024 का अंतरिम बजट प्रशासनिक रिवायत है क्योंकि पूर्ण बजट तो जुलाई में आएगा, जिस पर नई सरकार का रिपोर्ट कार्ड स्पष्ट नजर आएगा। व्यवसायों को फलने-फूलने के लिए सक्षम वातावरण बनाने, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग के उत्थान की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास न्यायसंगत, टिकाऊ और हरित हो, विकास की गुणवत्ता पर ध्यान दें। सरकार को बड़ी-बड़ी योजनाओं पर ध्यान देने की बजाय स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों में व्यापक सुधार पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि ये गरीबों के लिए महत्त्वपूर्ण योजनाएं हैं, लेकिन तथ्य यह भी है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा बजट अपर्याप्त हैं, भले ही ये सेवाएं खराब बुनियादी ढांचे, भारी रिक्तियों और अपर्याप्त संसाधनों से ग्रस्त हैं।

प्रियंका सौरभ, ई मेल से

शहर पहुंचे बच्चों की दुविधा

कहा जाता है, भारत गांवों का देश है। हमारी आबादी की 70% जनसंख्या गांवों में रहती है। वर्तमान समय में यह संख्या शहरीकरण के कारण और घट गई है। आज हर मिनट 20-25 व्यक्ति शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। कोई रोजगार के लिए, कोई अध्ययन के लिए, कोई शहर की सुख-सुविधाओं के लिए। हम उन छात्रों की स्थिति का वर्णन करना चाहते हैं, जो मध्यम और निम्न आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के हैं, और इंटरमीडिएट पास कर उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए सपना और उम्मीद लिए शहर आते हैं। जैसे ही बच्चा शहर में पहुंचता है, वहां की चकाचौंध को देख अपने सपने बुनने लगता है। लेकिन उसके सामने पहली दुविधा भाषा और वेशभूषा की आती है। इस कारण वह बच्चा, जो गांव में हो सकता हो हर गतिविधि में आगे हो, शहर आते ही अपने विचारों को दबाने लगता है। स्थिति तब और दयनीय हो जाती है, जब बच्चा हिंदी माध्यम का हो। वह सोचता है कि यदि कक्षा में अपने विचार रखेगा तो लोग हसेंगे। एक-दो बार प्रयास भी करता है, और वह इसको सही भी पाता है। फिर वो सोचता है कि शिक्षक उसका मार्गदर्शन करेंगे लेकिन उन्हें समय कहां कि वो एक-एक बच्चे पर समय दें। वो तो अपनी पदोन्नति (प्रमोशन) और अपना नाम बनाने में व्यस्त हैं। गुरु के लिए सभी समान हैं, लेकिन धरातल में ऐसा नहीं है।

शिवानी सिंह, शोधार्थी, लखनऊ विश्वविद्यालय

letter.editorsahara@gmail.com

राष्ट्रीय सहारा
राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

वर्ष-33, अंक 174

आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

For More Newspapers And Magazines Join Paid Group Whatsapp To 8969469464

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 5 फरवरी, 2024

दैनिक जागरण

सुधार का आरंभ स्वयं से ही किया जाना चाहिए

आवश्यक कदम

भर्ती परीक्षाओं में धांधली और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए एक नया कानून बनाने की केंद्र सरकार की तैयारी समय की आवश्यकता है। आशा की जा रही है कि इस तरह का कोई कानून संसद के इसी सत्र में आ सकता है, क्योंकि बजट सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने यह स्पष्ट किया था कि सरकार परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए कानून लाने जा रही है। ऐसे कानून की आवश्यकता इसलिए बढ़ गई है, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामले थमते नहीं दिख रहे हैं। भर्ती परीक्षाओं में धांधली होना अथवा उनके प्रश्नपत्र लीक हो जाना बहुत आम हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों में कई भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हो चुके हैं या फिर उनमें धांधली के मामले सामने आए हैं। जब ऐसा होता है तो केवल परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर ही प्रश्नचिह्न नहीं लगता, बल्कि लाखों छात्रों के संसाधन एवं समय की बर्बादी भी होती है। परीक्षा प्रणालियों के संदर्भ में जितना यह जरूरी है कि उनका संचालन पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता के साथ किया जाए, उतना ही यह भी कि वे युवाओं को भरोसा दिलाने वाली हों कि उन्हें उनके प्रयासों का उचित प्रतिफल मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित है।

यह ठीक है कि कुछ राज्यों ने भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं और ऐसी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई भी की है, लेकिन यह कहना कठिन है कि भर्ती परीक्षाओं में सेंध लगाने वालों के दुस्साहस का दमन हो पा रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वालों के संगठित गिरोह तैयार हो चुके हैं। ये गिरोह रह-रहकर परीक्षाओं को निशाना बनाते रहते हैं। ऐसे गिरोह अथवा धांधली करने वाले तत्व परीक्षाओं की विश्वसनीयता को प्रणाली के अंदर और बाहर, दोनों स्थानों से नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे तत्वों को इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती कि वे ईमानदारी से परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहें। फिलहाल यह कहना कठिन है कि केंद्र सरकार भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए जो कानून लाने की तैयारी कर रही है, उसका रूप-स्वरूप क्या होगा और वह पर्याप्त प्रभावी सिद्ध हो सकेगा या नहीं। ऐसे में आवश्यकता केवल इसकी नहीं है कि भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए कोई प्रभावी कानून लाया जाए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उस पर सही ढंग से अमल भी हो। अमल की यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों को उठानी होगी। आज के तकनीकी युग में यह आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य है कि भर्ती परीक्षाओं का संचालन उनकी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए किया जाए।

रिश्तों की हत्या

उत्तर प्रदेश में पौने तीन बीघा भूमि के लिए तीन लोगों की हत्या कर दी गई। लखनऊ के मलिहाबाद में हुई इन हत्याओं से अनेक प्रश्नों का प्रसव होता है। विवाद बंटवारे का था। मुकदमा निर्णीत हो चुका था और कुछ पक्षकारों ने (जिनके बीच खून का रिश्ता था) इसे आयुक्त कार्यालय में अपील में डाला था। करीब 10 साल बाद नौबत पैमाइश की आई। लेखपाल बिना पुलिस को सूचना दिए नापजोख को पहुंच गए। मौके पर विवाद हुआ और गुस्सा घर पर निकला, जहां एक पक्ष ने अपने ही भाई की पत्नी, बेटे और एक अन्य भाई की हत्या कर दी। बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर लोभ की वह कौन सी पराकाष्ठा है, जहां भूमि के एक टुकड़े के लिए अपने ही अपनों का खून बहाने में संकोच नहीं करते। एक जान की कीमत एक बीघा जमीन भी नहीं! वह भी तब जब परिवार के सभी लोग संपन्न हैं और कई सदस्य यूरोप के देशों में रहते हैं। प्रश्न यह भी है कि तमाम सुरक्षात्मक विधियों की उपस्थिति के बाद भी एक पीढ़ी अपनी विरासत अगली को अपनी आंखों के सामने सौंपने में संकोच क्यों करने लगती है? रिश्तों के जिन पौधों को व्यक्ति उम्रभर सींचता है, छायादार होने के बाद उनसे धूप आने के बजाय अंधकार गहराता क्यों प्रतीत होने लगता है। यह कड़वी सच्चाई है कि उम्र के अंतिम पड़ाव में बुजुर्ग इस भय में जीने लगते हैं कि कहीं संपत्ति भावी पीढ़ी को सौंपने के बाद वह उन्हें अकेला न छोड़ दें। दूसरा पक्ष यह है कि भावी पीढ़ी घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद पाने के बजाय उनकी संपत्ति पर आंखें गड़ाने लगती है। यह प्रवृत्ति अपवाद रही है, लेकिन बिखरते परिवारों और पलायन के कारण अब सिद्धांत बनती जा रही है। एक पक्ष प्रशासनिक खामियों का भी है। इस दिशा में वर्तमान सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसमें घरौनी की व्यवस्था, वरासत दर्ज कराने के नियम आसान करना, संपत्ति को खून के रिश्तों में नामांतरण पर स्टांप ड्यूटी न्यून करना शामिल हैं। किंतु लोभ की वासना प्रशासनिक सुधारों से नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक संस्कारों की स्थापना से ही दूर होगी।

महिला सशक्तीकरण को समर्पित सरकार

स्मृति इरानी

आज महिला-प्रधान विकास केवल कुछ कार्यक्रमों तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्र की विकास गाथा के केंद्र में खड़ा है

अवधेश राजपूत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज एक समावेशी राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, जिसमें लैंगिक समानता को महत्व दिया जा रहा है। महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रभावी नीतियां अपनाकर भारत की विकास गाथा में एक नया आयाम जोड़ा जा रहा है। पूर्व में लैंगिक समानता के मोर्चे पर निराशा की स्थिति थी, लेकिन आज उसकी जगह लोकतांत्रिक नीतियों और उनके सफल कार्यान्वयन ने ले ली है। आज शासन-प्रशासन के ढांचे में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और उनका कार्यालय कठिनाई से अर्जित इस संप्रभुता का प्रतीक है। उनकी आदिवासी पहचान राष्ट्रपति के पद को और भी गौरवशाली बनाती है। अंतरिम बजट में उनकी अध्यक्षता एक अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण रहा। यह ऐतिहासिक क्षण 75वें गणतंत्र दिवस के साथ मेल खाता है, जो समानता और न्याय के सिद्धांतों को मूर्त रूप देता है। 75 वर्षों के बाद भाजपा सरकार में महिलाओं को जल, थल, नभ और अंतरिक्ष सहित सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होते देखा जा रहा है। इक्कीसवीं सदी महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किए गए विचारशील सुधारों का पड़ाव है। महिलाओं के जीवन में भाजपा सरकार में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। जैसे 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण, 30.64 करोड़ मुद्रा लोन के वितरण और उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे वाली 10.1 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध होना है। प्रजनन अधिकारों पर भी अब खुलकर चर्चा हो रही है। हालिया बजट घोषणाओं के अनुसार 36 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया गया है। यह सभी सामाजिक वर्गों की महिलाओं के प्रति मोदी जी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यह दृष्टिकोण भारतीय महिलाओं की व्यावसायिक क्षमता का उपयोग करके तीन करोड़ महिलाओं को उद्यमी बनाने पर केंद्रित है। इन उद्यमियों को 'लखपति दीदी' के रूप में जाना जाएगा। इन महिलाओं के प्रति वर्ष एक लाख रुपये या उससे अधिक की आय अर्जित करने की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को बदलने के लिए, 'ड्रोन दीदी' योजना से कृषि के तौर-तरीके आधुनिक होंगे और पैदावार भी बढ़ेगी। महिलाओं के लिए ऐसी पहल 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने और प्रधान सेवक के तौर पर देश की सेवा पर जोर देने से हुई। महिलाओं के लिए विधायिका में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना और अनुच्छेद 370 को समाप्त करना क्रमशः महिलाओं की समान भागीदारी को बढ़ावा देने और संपूर्ण राष्ट्र को एकजुट करने की ओर प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिंग-समावेशी निधि को शामिल करना प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता को दर्शाता है। यह निधि बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण के लिए निरंतर हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है। 15वें वित्त आयोग ने भी अंतर-सरकारी राजकोषीय हस्तांतरण फार्मूले में लैंगिक पहलू को शामिल किया है, जिससे भारत में लैंगिक न्याय के लिए एक मजबूत आधार बना है। इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। अनुसंधान एवं नवाचार में एक लाख करोड़ का निवेश दिखाता है कि आज का भारत तेजी से विकास की नई बुलंदियों पर स्वयं को स्थापित कर रहा है। उल्लेखनीय है कि सभी एसटीईएम (साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स) स्नातकों में 43 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो कई विकसित देशों से कहीं आगे हैं।

भारत सरकार ने 2024-25 के बजट में महिलाओं के विकास और कल्याण पर खर्च को पिछले साल के मुकाबले 38.7 प्रतिशत बढ़ा दिया है। जेंडर बजट स्टेटमेंट के अनुसार 2024-25 में 43 मंत्रालयों/विभागों/केंद्र शासित प्रदेशों को 2023-24 की तुलना में आवंटन 38.6 प्रतिशत अधिक बढ़ा है। इसके परिणामस्वरूप कुल केंद्रीय बजट में लैंगिक बजट का हिस्सा पांच प्रतिशत से बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गया है। यह प्रतिबद्धता केवल घरेलू क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे जी-20 अध्यक्षता के दौरान नई दिल्ली घोषणा जैसी नीतियों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आगे बढ़ाया गया है। कोविड काल की विषम परिस्थितियों के दौरान जिस समय शीर्ष पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थीं, तब भी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही। जी-20 का नई दिल्ली घोषणापत्र आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण, लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटने, लैंगिक-समावेशी जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने और महिलाओं की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। यह वैश्विक लैंगिक समानता के लिए भारत के समर्पण का प्रमाण है। विश्व आर्थिक मंच पर भारत की प्रभावशाली उपस्थिति इसे लैंगिक सशक्तीकरण के एक मजबूत समर्थक के रूप में प्रतिबिंबित करती है।

नीति-निर्माण में महिलाओं को परंपरागत रूप से सूक्ष्म आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री के दूरदर्शी दृष्टिकोण ने इस दिशा में व्यापक आर्थिक प्रभाव डाला है। स्वास्थ्य, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक समानता को न केवल स्वीकार किया गया है, बल्कि इसे शासन ढांचे में भी संबोधित किया गया है। मोदी जी ने महिलाओं को जिम्मेदारियां सौंपकर इस दृष्टिकोण पर काम किया है और विभिन्न क्षेत्रों में सार्थक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और सामाजिक स्तर के निचले पायदान पर महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। आज महिला-प्रधान विकास केवल कुछ कार्यक्रमों तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्र की विकास गाथा के केंद्र में खड़ा है।

महिलाओं के नेतृत्व में विकास केवल जटिल योजनाओं तक सीमित न होकर राष्ट्र की प्रगति गाथा की नींव रखने वाला है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पहल को सफल बनाना और महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित किया जाना दर्शाता है कि प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया विजन में नारी शक्ति की उपस्थिति को अभूतपूर्व महत्व दिया जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में लैंगिक न्याय की ओर उठाए जा रहे कदम राष्ट्र को ऐसे युग की ओर ले जा रहे हैं, जहां मात्र खोखले राजनीतिक प्रलोभन नहीं, बल्कि प्रभावी कार्रवाई के लिए कदम उठाए जाते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश समावेशी विकास के साथ प्रगति के नए आयाम गढ़ रहा है।

(लेखिका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं)
response@jagran.com

प्रतिस्पर्धा पर सोच बदलने की जरूरत

'मम्मी-पापा सारी, आइ एम लूजर। मैं जेईई नहीं कर पाई। इसलिए सुसाइड कर रही हूं। यही लास्ट आप्शन है।' इन पंक्तियों के साथ न जाने कितनी पीड़ा लेकर पिछले दिनों एक बच्ची निहारिका ने अपना जीवन खत्म कर लिया। वह कोटा में रहकर एक कोचिंग सेंटर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। कोटा में बीते सप्ताह आत्महत्या की यह दूसरी घटना है। इससे पहले नीट की तैयारी कर रहे मोहम्मद जैद ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसा सिर्फ कोटा में ही नहीं हो रहा है। ऐसे हादसे पूरे भारत या कहें विश्व में घटित हो रहे हैं और हम किंकर्तव्यविमूढ़ बने ये सब घटित होते हुए देख रहे हैं। क्या इसके लिए पूरा समाज जिम्मेदार नहीं है? या फिर हम घोर स्वार्थी हो इसे बच्चों की मानसिक कमजोरी मानकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। घर के भीतर और बाहर अनकहे दर्द से भरी तमाम आंखें हमारी ओर देख रही हैं, पर हम अपनी आकांक्षाओं के आगे बच्चों की उस पीड़ा को अल्पकालिक समझ उन पर निरंतर दबाव बनाए जा रहे हैं। जब अभिभावक और समाज बच्चों के जीवन की कीमत पर अपनी महत्वाकांक्षाओं के घोड़े दौड़ा रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि यह सामाजिक-सांस्कृतिक विध्वंस की पराकाष्ठा है।

विगत एक दशक में युवाओं की आत्महत्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत में पिछले एक दशक में आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या में सत्तर प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं अमेरिका में पिछले दो दशकों में युवाओं में आत्महत्या की दर में 62 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अमूमन सभी देश युवा आत्महत्या के संदर्भ में एक ही पायदान पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। हाल में 'एनल्स आफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ' में एक शोध प्रकाशित हुआ, जिसमें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। इसमें वर्षों तक बच्चों के भीतर पनप रहे अवसाद, चिंता और आत्मघाती विचारों और व्यवहारों की तीव्रता के संबंध में गहन अध्ययन किया गया है। लास एंजिलिस स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की मनोचिकित्सक प्रोफेसर जोसेलीन मेजा कहती हैं कि 'हम व्यक्तिगत स्तर पर लक्षणों को कम करने पर बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन उन कारणों की अवहेलना कर रहे हैं, जो कि प्रणालीगत हैं। हम वास्तव में सामाजिक संरचनाओं की अनदेखी कर रहे हैं।' यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि आत्महत्या जिसे हम अमूमन 'व्यक्तिगत क्रिया' मानकर विश्लेषित करते हैं वह एक 'सामाजिक क्रिया' है। समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम ने भी अपनी पुस्तक 'सुसाइड' में इस विषय पर गहन शोध के पश्चात यह स्पष्ट किया है कि सामाजिक तानाबाना तथा परिस्थितियां किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए विवश करती हैं।

डा. ऋतु सारस्वत

युवाओं की आत्महत्या का कारण उपलब्धि वाली संस्कृति है। यह उन्हें एक मशीन से अधिक कुछ नहीं समझती

बच्चों पर न डालें अनावश्यक दबाव। फाइल

अगर इस दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर बच्चों के जीवन को करीब से देखा जाए तो कुछ तथ्य स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे-बच्चे तनाव और अवसाद में हैं। अवसाद कोई बाहरी तत्व नहीं है। यह आंतरिक रूप से शुरू होता है और इसकी जड़ में घोर अकेलापन, लक्ष्यों के प्रति भ्रम और सामाजिक दबाव हैं। बच्चों के भीतर पल रहे अवसाद का केंद्र मूलतः 'उपलब्धि संस्कृति' है, जो इतनी विषाक्त हो चुकी है कि वह बच्चों को एक मशीनी-संरचना से अधिक कुछ नहीं समझती। उपलब्धि वाली संस्कृति उन पर 'सर्वश्रेष्ठ' होने का दबाव बनाती है। यह उन पर प्रतिस्पर्धी दौड़ में सम्मिलित होने के लिए दबाव बनाती है, जहां जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण 'सफलता' है। बच्चों के जीवन की प्रत्येक दिन की गणितीय गणना जिस प्रकार से अभिभावक करते हैं वहां बच्चों के लिए सांस लेने की भी जगह दिखाई नहीं देती। सर्वोच्च उपलब्धि हासिल करने का दबाव बच्चों के संगी-साथी सभी को अलग कर देता है। परिवार और समाज से प्राप्त इस संदेश को बच्चे आत्मसात कर रहे हैं कि उनकी 'उपलब्धियों' के अलावा उनका कोई 'मूल्य' नहीं है।

अभिभावक ही क्यों, संपूर्ण संस्कृति अलग-अलग स्तरों पर एक दबाव समूह की तरह कार्य कर रही है। 'नेवर इनफःव्हेन अचीवमेंट कल्चर बिकम्स टाक्सिक-एंड व्हाट वी कैन डू अबाउट इट' नामक पुस्तक में परिवार, शिक्षकों के साथ-साथ लगभग छह हजार से अधिक माता-पिता से साक्षात्कार के बाद उन तथ्यों को उजागर किया गया है, जिनसे परिचित होना जरूरी हो जाता है। पुस्तक की लेखिका जेनिफर ब्रेहेनी वालेस के अनुसार, 'लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है। उच्च प्रदर्शन का दबाव सिर्फ माता-पिता का मसला नहीं है, अपितु प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से यह दबाव समाज का बनाया हुआ है।' सबसे दुखद यह है कि व्यवस्थाओं को कोसते अभिभावक यह भूल जाते हैं कि हर बच्चा स्वयं में विशेष है और उसकी अपनी कुछ विशिष्टताएं हैं। यह भी विस्मृत करने योग्य नहीं है कि सफलता खुशी का मापदंड नहीं है। अगर ऐसा होता तो सफल होने का एक तथाकथित मापदंड 'आइआइटी' अपने 33 विद्यार्थियों की पिछले पांच वर्षों में आत्महत्या का साक्षी नहीं बनता। अगर 'धन' वास्तव में संतुष्टि और सफलता का मापदंड होता तो कैलिफोर्निया के पालो आल्टो में युवा आत्महत्या दर राष्ट्रीय स्तर की तुलना में चार गुना अधिक नहीं होती, जहां औसत घरेलू आय दो लाख डालर है। अभी भी समय है कि समाज और अभिभावक अवलोकन करें कि सर्वश्रेष्ठता की जो परिभाषा वे आत्मसात किए बैठे हैं, कहीं वही उनकी सबसे बड़ी असफलता तो नहीं।

(लेखिका समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

वाणी का सदुपयोग

शब्द मनुष्य के विचार और भावना के आदान-प्रदान का प्रभावी वाहन हैं। लिखित शब्दों के प्रयोग में विचार या मंथन आवश्यक होता है। हालांकि आज के सुविधा उन्मुख और जल्दबाजी के दौर में जहां बोलने से कार्य सध जाए, लोगों में लिखित शब्दों के प्रयोग से बचने की प्रवृत्ति अधिक है। समझने के लिए बोलने से अधिक सुनना आवश्यक है। हमारी दो-दो आंखें और कान इसलिए हैं कि हम अधिक देख-सुन कर परिस्थितियों का आकलन बेहतर कर सकें। जिह्वा एक इसलिए है कि बोलें अधिक नहीं। कुछ परिस्थितियों में अपनी मंशा दूसरों तक पहुंचाने में मौन अधिक प्रभावशाली होता है। अधिक बोलेंगे तो अनावश्यक शब्द या अपशब्द फूट पड़ेंगे, मनमुटाव की आशंका रहेगी।

शब्द में राहत देने और आहत करने की अपार क्षमता है। अल्पभाषी का व्यक्तित्व संवरा, संयत होता है। दुर्भाग्य है कि लोकजीवन में अधिक बोलने की प्रवृत्ति व्यापक व्याधि का रूप ले चुकी है। चलते-फिरते, पढ़ते-लिखते, खाते-पीते, वाहन में बैठे या वाहन चलाते, मोबाइल पर या वैसे भी या पूजा के दौरान भी, बोलते रहने वाले बहुतेरे दिखते हैं। ऐसा व्यक्ति कहीं भी, कुछ भी कहने से नहीं चूकेगा। वहीं पूर्ण चुप्पी साध लेंगे तो अनेक कार्य अवरुद्ध हो जाएंगे, हर्षोल्लास, चिंताएं, साझा नहीं होंगी। मन और चित्त अस्वस्थ हो सकते हैं। हमारी अधिकांश समस्याएं अधिक बोलने या बिल्कुल नहीं बोलने से हैं। दुनिया के आधे व्यक्तियों के पास कहने को बहुत कुछ है, किंतु स्वभाव, लिहाज, भय या अन्य कारणों से वे मौनी बन गए हैं। शेष आधे वे हैं जो सदा कुछ भी निरर्थक बोलते रहते हैं। बोलने और नहीं बोलने में उचित संतुलन आवश्यक है। कहां कब, क्या और कितना बोलना है और कहां बोलना ही नहीं है, यह समझ लेंगे तो जीवन संतुष्टिमय हो जाएगा।

हरीश बड़थ्वाल

सर्विकल कैंसर का बढ़ता खतरा

सोनम लवंशी

सर्विकल कैंसर महिलाओं के लिए गंभीर समस्या है। इससे बचाव के लिए सार्थक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है

बीते दिनों बालीवुड एक्ट्रेस और माडल पूनम पांडे ने सर्विकल कैंसर पर अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर सनसनी फैला दी। पूनम पांडे का कृत्य निंदनीय है। निश्चित रूप से यह कैंसर पीड़ितों का अपमान है। सर्विकल कैंसर देश की महिलाओं के लिए गंभीर समस्या है। इससे बचाव के लिए सार्थक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में देश में 15 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं पर न केवल सर्विकल कैंसर का खतरा मंडरा रहा है। बल्कि हर साल 77 हजार महिलाओं की इस बीमारी से मौत हो रही है। यानी हर दिन करीब 211 महिलाएं सर्विकल कैंसर के कारण अपनी जान गंवा रही हैं। साल 2020 में पूरी दुनिया में महिलाओं में सर्विकल कैंसर के 6,04,000 मामले सामने आए, जिनमें से 3,42,000 मरीजों की मौत हो गई। भारत में सर्विकल कैंसर महिलाओं में पाए जाने वाले कैंसर का दूसरा सबसे प्रचलित रूप है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सर्विकल कैंसर की इसी गंभीरता को देखते हुए अंतरिम बजट में इसके लिए टीकाकरण कार्यक्रम का एलान किया है। उन्होंने देश में नौ से 14 वर्ष की बच्चियों को सर्विकल कैंसर की वैक्सीन दी जाने की बात कही हैं।

मेडिकल जर्नल 'द लैंसेट' की एक रिपोर्ट की मानें तो दुनिया में सर्विकल कैंसर से पीड़ित महिलाओं की मौत के मामले में भारत पहले नंबर पर है। दुनिया में हर पांच में से एक सर्विकल कैंसर से ग्रस्त महिला भारतीय है। हमारे देश में सिर्फ एक प्रतिशत महिलाओं की सर्विकल कैंसर की जांच हो पाती है जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कम से कम 70 प्रतिशत महिलाओं की टेस्टिंग होनी चाहिए।

ब्रेस्ट कैंसर हो या सर्विकल कैंसर महिलाओं के लिए, दोनों ही बीमारियां जानलेवा साबित हो रही हैं। महिलाएं सामाजिक तौर पर इस बीमारी के बारे में बात करने में शर्म महसूस करती हैं। सरकार द्वारा भी पूर्व में इसे लेकर उतनी गंभीरता नहीं दिखाई गई, लेकिन अब उसने प्राथमिक स्तर पर जागरूकता लाने के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया है। डाक्टरों की मानें तो सही समय पर जागरूकता और सही इलाज से महिलाओं की जान बचाई जा सकती है। इस वक्त सर्विकल कैंसर से पीड़ित महिलाओं को नया जीवन कैसे मिल सकता? इस पर चर्चा होनी चाहिए। महिलाओं को असुरक्षित यौन संबंधों से बचने की भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक से अधिक पार्टनर होने से सर्विकल कैंसर का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा सरकार को जांच का दायरा बढ़ाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ एक प्रतिशत महिलाओं की जांच होने से समस्या से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

आत्मविश्वास से भरा अंतरिम बजट

'आत्मविश्वास से भरी मोदी सरकार' शीर्षक से लिखे आलेख में संजय गुप्त ने वर्तमान सरकार के अंतिम और अंतरिम बजट को ठोस और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी बताया है। जैसा कि अनुमान था कि इस बजट को मोदी सरकार चुनाव जीतने के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह उपयोग करेगी, लेकिन सारे अनुमान और विशेषज्ञों की राय पूरी तरह गलत साबित हो गई। इसका कारण मोदी सरकार के जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाले वे कार्य हैं जिसने भारत की जनता के जीवन स्तर को पूरी तरह बदल दिया है। जहां एक तरफ औसत महंगाई की दर में रुकावट आई है तो दूसरी तरफ भारत देश विकास के मार्ग पर तेजी से चल पड़ा है। अंतरिक्ष अनुसंधानों सहित अनेकानेक क्षेत्रों में देश ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की है, जो वाकई सराहनीय है, परंतु भारतीय किसानों की स्थिति में अभी बहुत उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया है। गरीबी की मार झेल रहे किसानों को उम्मीद थी कि उसे दी जा रही मदद यथा किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन सरकार ने उन्हें निराश किया है।

वेदप्रकाश पाडेय, अंबेडकर नगर, उप्र

मोदी सरकार का आत्मविश्वास

संजय गुप्त का आलेख ''आत्मविश्वास से भरी मोदी सरकार' बहुत ही उत्तम है। यह आत्मविश्वास वास्तविकता पर आधारित है। आइएनडीआइए में लोकप्रियता के मानदंड पर नरेन्द्र मोदी के नजदीक कोई नहीं ठहरता। वैसे भी आइएनडीआइए अभी तक प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित नहीं कर पाया है। संसद में वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा पेश अंतरिम बजट में पहले की तरह एक भी लोकलुभावन वादा या फ्री की रेवड़ी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव उपरांत पूर्ण बजट में बड़ी घोषणाएं की जाएंगी। मोदी सरकार का यह आत्मविश्वास पिछले दस वर्षों में जनकल्याण और राष्ट्र उत्थान के लिए किए गए कार्यों के कारण है। विशेष तौर पर 2020-21 में कोविड प्रबंधन पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ था। यह विशाल जनसंख्या और कमजोर स्वास्थ्य ढांचे की चुनौती होने के बावजूद हुआ। आज भारत विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। हमारा देश पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने को अग्रसर है। अंतरिम बजट से स्पष्ट है कि मोदी का भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का दावा कल्पना नहीं, एक वास्तविकता है। लंबे समय तक कामयाबी के लिए जमीन से जुड़े कार्य करने होते हैं। मोदी सरकार ने जमीन से जुड़े अनेकों कार्य किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण एवं अभूतपूर्व कार्य उनके किसी मंत्री, सांसद, विधायक स्तर पर एक भी भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आना है। कांग्रेस और अधिकतर विपक्षी दल जाति एवं क्षेत्रवादी राजनीति कर रहे हैं। मोदी ने इस घातक जातिवादी एवं क्षेत्रीय राजनीति को तिलांजलि देकर चार वर्गों गरीब, महिलाओं, युवा और किसानों के कल्याण एवं उत्थान की राजनीति शुरू की है। इसका अधिकतर जनमानस स्वागत कर रहा है। मोदी सरकार का आत्मविश्वास वास्तविक और सच्चाई पर आधारित है।

सीपी बंसल, दिल्ली

मेलबाक्स

सही हाथों में सम्मान

संपादकीय 'भारत रत्न आडवाणी' में भाजपा के बड़े योद्धा लालकृष्ण आडवाणी को भारतीय राजनीति का बेमिसाल तारा बताते हुए उचित लिखा गया है कि आडवाणी ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रति अपराधबोध रखने वालों को जागृत किया। अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो चुकी है। रामलला वहां विराजमान हो चुके हैं। अब मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया है। आडवाणी साल 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित जनसंघ से जुड़े। 1977 में जनता पार्टी से जुड़े। फिर 1980 में भाजपा की स्थापना की। आडवाणी जब 14 साल के थे, तभी संघ से जुड़ गए थे। राजनीति में प्रवेश के बाद आडवाणी ने राजनीति की धारा बदल दी।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

50.21 लाख बेसहारा पशुओं की संख्या है देशभर में, भारत सरकार द्वारा जारी वर्ष 2019 में बीसवीं पशु धन गणना की रिपोर्ट के अनुसार। इसमें राजस्थान पहले और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है।

विवेक ओझा
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार

लाल सागर

क्षेत्रीय राजनीति का हथियार हाउती लड़ाके

लाल सागर में हाउती लड़ाकों का व्यापारिक समुद्री जहाजों पर हमला महज जहाज लूटने और उसे नष्ट करने तक सीमित नहीं है। यह पश्चिम एशिया की क्षेत्रीय राजनीति को हवा देने का जरिया बन गया है। इजरायल के फलस्तीन, ईरान, सीरिया, जार्डन, मिस्र से रिश्ते कैसे हैं और कैसे होने चाहिए, हाउती ने अपने हमलों से इसे चर्चा का विषय बना दिया है। ऐसे में अमेरिकी गुट, इजरायल और अन्य सहयोगी देशों की यह जिम्मेदारी है कि कूटनीति के जरिये यह सुनिश्चित हो कि कोई भी पक्ष गैर-जिम्मेदाराना कार्य न करे

वैश्विक तेल व्यापार का 12 प्रतिशत हिस्सा लाल सागर के जरिये होता है, इसलिए हाउती इन जहाजों को अधिक निशाना बनाते हैं। फाइल

जर्मनी के प्रसिद्ध सैन्य सिद्धांतकार कार्ल वान क्लाटविट्ज ने ठीक ही कहा था कि राजनीति वह गर्भाशय है जिसमें युद्ध विकसित होता है। लाल सागर में हाउती और पश्चिमी ताकतों के बीच छिड़ी जंग में यह बात बहुत हद तक सही दिखती है। अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिम एशिया की राजनीति को अपने चश्मे से देखते हैं, वहीं यहां की कुछ क्षेत्रीय शक्तियां पश्चिमी ताकतों खासकर अमेरिका और इजरायल के संदर्भ में 'प्रतिशोध और प्रतिरोध' का कठोर नजरिया रखती हैं। इसी रस्साकसी में सबसे गरीब अरब देश यमन के हाउती लड़ाकों ने लाल सागर क्षेत्र में गंभीर अस्थिरता उत्पन्न कर दी है। अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने सहयोगियों सहित हाउती ठिकानों पर मिलिट्री स्ट्राइक किए हैं। उत्तरी यमन के 13 जगहों पर 36 हाउती ठिकानों पर अमेरिका और ब्रिटेन का ये हमला सिद्ध करता है कि समुद्री व्यापार को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों और इजरायल को सबक सिखाने के सोच से काम करने वाली ताकतों को मुंहतोड़ जबाव दिया जाएगा।

अमेरिका और ब्रिटेन ने कुछ ही दिनों पहले ईरान और सीरिया में सात स्थानों पर 85 हाउती ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं और साफ कर दिया है कि ईरान और सीरिया की धरती पर हाउती लड़ाकों का मनोबल नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ईरान और सीरिया यदि हाउती लड़ाकों को अपनी धरती पर सहयोग या समर्थन देते हैं तो उन्हें भी इसके परिणाम के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा हाउती के विरुद्ध किए गए ताजा हमले में आस्ट्रेलिया, बहरीन, डेनमार्क, कनाडा, नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड ने अपना सहयोग दिया है। इन देशों ने खुफिया जानकारी और लाजिस्टिक्स के मामले में सहयोग किए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में महाशक्तियों, ईरान, लेबनान जैसी क्षेत्रीय ताकतों और खासकर हाउती लड़ाकों को यह समझना जरूरी है कि इजरायल के द्वारा हमास और गाजापट्टी के खिलाफ कार्रवाई का जो जवाब लाल सागर में दिया जा रहा है, वह सही तरीका नहीं है और वह ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के विरुद्ध कार्रवाई के रूप में माना जा रहा है। इससे शक्ति ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलेगा। दो देशों के बीच शत्रुता के चलते होने वाला युद्ध थोड़े ही समय में वैश्विक राजनीति को नए मोड़ देने लगता है।

भारत के रक्षा मंत्रालय का निर्णय : मालवाहक जहाजों पर होने वाले हमले को रोकने और समुद्री लुटेरों पर लगाम को लेकर भारत सरकार ने भी बड़ा निर्णय लिया है। रक्षा मंत्रालय ने जिबूती से लेकर अदन की खाड़ी और सोमालिया तक भारतीय नौसेना की तैनाती का प्लान बनाया है। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। इसमें मालवाहक जहाजों के संरक्षण के लिए भारतीय नौसेना की यूनिट्स को जिबूती, अदन की खाड़ी, सोमालिया के पूर्वी तट के साथ ही उत्तर और मध्य अरब सागर में भी तैनात किया जा रहा है। नौसेना हमलों में शामिल सूत्रों और भागीदारों की पहचान करने के लिए सहयोगी देशों के साथ सूचना साझा कर रही है। नौसेना ने अदन की खाड़ी और अफ्रीका के पूर्वी तटीय क्षेत्र में जलदस्यु रोधी गश्ती के लिए 2008 से अपनी यूनिट्स को तैनात किया था। कुल 3,440 जहाजों और 25 हजार से अधिक नाविकों को सुरक्षा प्रदान की गई है। भारत पहले भी अदन की खाड़ी में पीआइ-8 सर्विलांस एयरक्राफ्ट तैनात कर चुका है। भारत का प्राथमिक उद्देश्य समुद्री डकैती (पायरेसी) और वाणिज्यिक समुद्री जहाजों पर होने वाले ईरान समर्थित हाउती के हमलों को रोकना है। इसके लिए भारत को कूटनीतिक स्तर पर ईरान को साथ रखना करना होगा। ईरान के आर्थिक लाभ भारत से जुड़े हैं, दोनों चाबहार पोर्ट जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना से जुड़े हैं। दोनों ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य रहे हैं। हालांकि ये बातें सैद्धांतिक लग सकती हैं, लेकिन जब भी कोई क्षेत्रीय संघर्ष समाधान करना होता है तो हर प्रकार के रास्तों को तलाश करना होता है और उनकी अपनी संभावनाएं होती हैं।

हाउती का उद्देश्य : हाउती यमन के अल्पसंख्यक शिया 'जैदी' समुदाय का एक हथियारबंद समूह है। पिछली सदी के अंतिम दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह के भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इस समूह का गठन किया था। उनका नाम उनके अभियान के संस्थापक हुसैन अल हूती के नाम पर पड़ा है। वे स्वयं को 'अंसार अल्लाह' यानी ईश्वर के साथी भी कहते हैं। वर्ष 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हुए हमले में हाउती विद्रोहियों ने नारा दिया था, 'ईश्वर महान है, अमेरिका का खात्मा हो, इजरायल का खात्मा हो, यहूदियों का विनाश हो और इस्लाम की विजय हो। हाउती स्वयं को हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजरायल, अमेरिका और पश्चिमी देशों के विरुद्ध ईरान के नेतृत्व वाली 'प्रतिरोध की धुरी' का हिस्सा बताया था। हाउती विद्रोही लेबनान के सशस्त्र शिया समूह हिजबुल्लाह के माडल से प्रेरणा लेते हैं। अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट 'कांबैटिंग टेररिज्म सेंटर' के अनुसार, हिजबुल्लाह ही उन्हें 2014 से बड़े पैमाने पर सैन्य विशेषज्ञता और ट्रेनिंग दे रहा है। हाउती स्वयं को ईरान का सहयोगी भी बताते हैं, क्योंकि उनका साझा दुश्मन है सऊदी अरब। हाउती उत्तरी यमन में सऊदी अरब द्वारा सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा के विस्तार के विरोध में हैं। यमन के सलाफियों का सऊदी अरब से मजबूत लिंक रहा है। हाउती शिया हमेशा सऊदी अरब के इस आयाम से शंका से भरे रहे हैं कि सऊदी सत्ता परिवर्तन में भी राजनीति कर सकता है। हाउती जैदी शिया मुस्लिम जो देश की आबादी का 35 प्रतिशत हैं, अपने देश में सऊदी अरब के सलाफी प्रभुत्व और अत्याचार की आशंकाओं के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए हाउती आंदोलन पिछली सदी के अंतिम दशक में एक कल्चरल रिवाइवलिस्ट आंदोलन के रूप में धार्मिक शुद्धता के लिए उभरा था।

कालांतर में हाउती को ईरान का साथ मिला। ईरान पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि हाउती विद्रोहियों को ईरान हथियार भी दे रहा है। यमन की अधिक आबादी हाउती विद्रोहियों के नियंत्रण में रहती है। उनका संगठन देश के उत्तरी हिस्से में टैक्स वसूलता है और अपनी मुद्रा भी छापता है। अमेरिका और सऊदी अरब कहते हैं कि ईरान ने हाउती विद्रोहियों को बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस किया था, जिनका उपयोग 2017 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हमले के लिए किया गया था। इन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया था। सऊदी अरब ने ईरान पर हाउती विद्रोहियों को क्रूज मिसाइल और ड्रोन देने का भी आरोप लगाया है।

हाउती विद्रोही सऊदी अरब पर कम रेंज वाली हजारों मिसाइल दाग चुके हैं और उन्होंने यूएई को भी निशाना बनाया है। इस तरह के हथियारों की सप्लाई करने का अर्थ है संयुक्त राष्ट्र की ओर से हथियारों पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करना, लेकिन ईरान इन सभी आरोपों को खारिज करता है। अपनी शक्तियों के दम पर हाउती विद्रोही लाल सागर के बड़े हिस्से को नियंत्रित करते हैं। यहां जहाजों को निशाना बनाना आसान होता है। दुनिया भर के तेल व्यापार का 12 प्रतिशत हिस्सा लाल सागर के जरिये ही आता-जाता है, इसलिए हाउती विद्रोही इन जहाजों को ज्यादा निशाना बनाते हैं। इसके जरिये वे पूरी दुनिया और खासकर सऊदी अरब पर दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि यमन की सरकार वहीं से चलती है। हाउती विद्रोही, सऊदी अरब से और छूट चाहते हैं। हमलों के जरिये वे यह जताना चाहते हैं कि वे कभी भी लाल सागर के रास्ते को बंद कर सकते हैं। ऐसा करने से तेल के कारोबार में रुकावट आएगी और दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ेंगे, जिस कारण सऊदी अरब पर और दबाव आएगा। वहीं, इजराइल के जहाजों को इसलिए निशाना बनाते हैं, क्योंकि हाउती स्वयं को हमास का समर्थक बताते हैं। ऐसे में इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के दौरान वे अपनी दोस्ती भी दर्शाना चाहते हैं।

भारतीय नौसेना की बढ़ती धमक

योगेश कुमार गोयल

भारतीय नौसेना में एक और बाहुबली योद्धा शामिल हो गया, जिसके बाद भारत की नौसैनिक ताकत और बढ़ गई है। भारतीय नौसेना के पहले सर्विलांस जहाज आइएनएस संधायक को समुद्र में भारत का 'गूगल मैप' बताया गया है। भारत का यह सर्वेक्षण जहाज समुद्र में भारतीय नौसेना की यात्रा को आसान तथा और ज्यादा आरामदायक बनाने में भूमिका निभाएगा व समुद्र में गूगल मैप की भांति कार्य भी करेगा। आइएनएस संधायक भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। इसे अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है, जो इसे उपयोगी बनाते हैं। इसमें लगाए मल्टी-बीम इको-साउंडर्स समुद्र तल की गहराई का सटीक चित्रण प्रदान करते हैं, जबकि उपग्रह-आधारित पोजीशनिंग सिस्टम जहाज की सटीक स्थिति निर्धारित करते हैं। साइड स्कैन सोनार समुद्र तल की सतह और नीचे की वस्तुओं का पता लगाते हैं।

आइएनएस संधायक आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता का एक वास्तविक प्रमाण है। समुद्री क्षेत्रों की निगरानी करने और खतरों का पता लगाने में यह भूमिका निभाएगा, जिससे समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी। चीन तथा अन्य क्षेत्रीय देशों के बढ़ते समुद्री दबाव का सामना करने और हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ने हाल के वर्षों में अपनी नौसेना के बेड़े में कई नए युद्धपोत, सबमरीन, विमान इत्यादि शामिल किए हैं, जिनमें विमानवाहक पोत आइएनएस विक्रांत, स्वदेशी पनडुब्बियां, उन्नत मिसाइल विध्वंसक और फ्रिगेट्स शामिल हैं। नौसेना के बेड़े में इनकी उपस्थिति से भारतीय नौसेना की ताकत और क्षमताओं में काफी वृद्धि हुई है और भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अब एक शक्तिशाली और सक्षम बल है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

खरी-खरी

आदमी का गिरगिट हो जाना

डा. प्रदीप उपाध्याय

हाल ही में उनकी प्रजाति के एक आदमी ने रंग बदला तो उनके साथ में बहुतेरे लोगों के रंग अपने आप बदल गए। उनमें और गिरगिट में बहुत साम्य है। हालांकि वे गिरगिट नहीं हैं, उन्हें ऊपर वाले ने दोपाया बनाया है, तब भी उन्होंने गिरगिट हो जाने का वरदान प्राप्त कर लिया है। आदमी का गिरगिट बनना हर किसी के लिए संभव भी नहीं है, हर कोई बन भी नहीं सकता। एक प्रजाति विशेष ही धारणाधिकार रखती है गिरगिट की भांति हो जाने का।

आम आदमी के लिए तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि वह गिरगिट हो जाए। यह आम आदमी वह वाला आम आदमी नहीं है जो महज आम आदमी की टोपी पहन कर ही आम आदमी बना हुआ है। वरना तो टोपी वाला आम आदमी खासमखास है। बहरहाल, आम आदमी के पैरोकार गिरगिट हो जाने के लिए स्वतंत्र हैं, उन्हें ऐसा हो जाने से रोकने की क्षमता आम आदमी तो ठीक, उस ऊपर वाले में भी नहीं है। क्योंकि ऊपर वाला तो एक बार बनाकर उसे जमीन पर छोड़ देता है, उसके बाद तो वह स्वयं बेबस हो जाता है, उसके स्वयं के वश में भी नहीं रहता कि वह आदमी को आदमी ही बना रहने दे। यह विशेषज्ञता तो आदमी स्वयं हासिल कर लेता है कि वह आदमी रहते हुए गिरगिट हो जाए।

वह समय की नजाकत के साथ गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेता है। यह विशेषता आदमी और गिरगिट के अलावा किसी सरीसृप के पास नहीं होती है। जिस तरह से गिरगिट की स्किन ट्रांसपेरेंट होती है, यह पिगमेंट दानेदार होती है, जो शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है और जब गिरगिट की कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो ये दाने एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। इससे इसकी त्वचा का रंग काला हो जाता है और जब ये तितर-बितर हो जाते हैं तो रंग बदल जाता है। ठीक इसी तरह वे भी अपने हाव-भाव, कार्य-व्यवहार, सोच पिगमेंट दानों की तरह तितर-बितर करते रहते हैं और उनका रंग बदलता हुआ दिखाई दे जाता है। तब भी जिस तरह से गिरगिट, गिरगिट ही बना रहता है, वे भी वही रहते हैं। क्या आपने उन्हें देखा है।

पोस्ट

पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न और उसके कुछ दिन बाद ही लालकृष्ण आडवाणी को देश का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ही दिनों में मंडल-कमंडल दोनों को एक साथ संदेश देकर साधने का प्रयास किया है।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

इन दिनों एक ओटीटी पर अलेक्जेंडर नाम की डाक्यूमेंट्री बहुत चर्चित हो रही है। उस संदर्भ में यही कहना है कि भारतीय सिनेमा में कोई स्कंदगुप्त को फिल्माने की पहल क्यों नहीं कर रहा है? नायकों का नायक और नर-कंकालों में मदिरापान करने वालों को भी सबक सिखाने वाला योद्धा। भारतीय इतिहास में उनका पर्याप्त महिमामंडन नहीं हुआ। आशीष नौटियाल@ashu_nauty

भारत की दोनों पारियां एक ही बल्लेबाज के इर्द-गिर्द केंद्रित रहीं। पहले यशस्वी जायसवाल और फिर शुभमन गिल। भारत ने काफी बढ़त बना ली है और एक ऐसी पिच पर जहां पेसर व स्पिन गेंदबाजों दोनों के लिए कुछ न कुछ मदद मौजूद है, वहां इंग्लैंड को जीत के लिए 399 रनों का पीछा करने के लिए असाधारण बल्लेबाजी करनी होगी। अयाज मेमन@cricketwallah

छत्तीसगढ़ डायरी

निकल पड़ी गारंटी की यात्रा

सतीश चंद्र श्रीवास्तव
संपादकीय प्रभारी, रायपुर

अयोध्या में रामलला का दर्शन कराने के लिए गारंटी की यात्रा निकल पड़ी है। लोकसभा चुनाव से पहले रविवार को 1,400 आस्थावान श्रद्धालुओं के साथ बढ़ी विशेष ट्रेन प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के चुनावी वादे को समयबद्धता के साथ पूरे किए जाने के चौतरफा प्रयास का हिस्सा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुसार सोमवार से महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी जिसके तहत प्रदेश की लगभग 75 लाख महिलाओं को मार्च से एक हजार रुपये प्रति माह मिलने शुरू हो जाएंगे। आठ मार्च को महिला दिवस से योजना को शुरू करने का प्रस्ताव है। आयकर की परिधि से बाहर प्रदेश के लगभग 50 लाख परिवारों की महिलाओं लिए यह बड़ा उपहार सिद्ध हो सकता है।

महतारी वंदन योजना में शामिल होने वाली महिलाओं की वास्तविक संख्या 20 फरवरी के बाद ही स्पष्ट होगी। यद्यपि किसानों को दिए जा रहे तोहफे के मुकाबले यह काफी कम रहेगा। दिसंबर महीने में प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई भाजपा ने सबसे बड़ा उपहार किसानों को दिया है। मंडियों में 3,100 रुपये की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी हो रही है। धान खरीदी के प्रति सरकार के उत्साहवर्धन ने पिछले सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य भले ही 2,183 रुपये प्रति क्विंटल तय कर रखा है, प्रदेश सरकार अपना वादा पूरा करने के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत बोनस के रूप में प्रति क्विंटल 917 रुपये अतिरिक्त देने जा रही है। वर्ष 2022-23 के 1,070 लाख क्विंटल के मुकाबले प्रदेश की मंडियों में 1,500 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीदारी हो चुकी है।

प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी खेती-किसानी से जुड़ी है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में धान का मुद्दा अगर कांग्रेस के 2,500 रुपये की दर से प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदी के वादे के पक्ष में गया था तो इस बार भाजपा ने धान पर ही बड़ा दांव खेलते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया। साथ में महतारी वंदन योजना की घोषणा ने रातों-रात समीकरण बदल दिए। लोकसभा चुनाव से पहले इन योजनाओं को लागू करना बड़ी चुनौती बनती जा रही थी। विपक्ष के नेताओं द्वारा दावा किया जा रहा था कि ऐसी योजनाओं को कुछ दिनों पहले तक मुफ्त की रेवड़ी बताने वाली भाजपा अपने वादों को समय से पूरा नहीं कर पाएगी। प्रदेश की आर्थिक स्थिति और लगातार बढ़ते कर्ज के बोझ को देखते हुए विशेषज्ञ भी आर्थिक दबाव की बात कर रहे थे।

किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनते प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। फाइल

दूसरी तरफ मुख्यमंत्री साय शपथ ग्रहण के बाद से ही मजबूती के साथ मोदी की गारंटियों को पूरा करने का दावा करते रहे हैं। इसकी शुरुआत ग्रामीणों के लिए 18 लाख पीएम आवास की घोषणा से हुई। पिछली सरकार के कार्यकाल में पूरी तरह से उपेक्षित रही पीएम आवास योजना ग्रामीण स्तर पर आंतरिक रोष का कारण रही। तेंदू पत्ता के लिए 5,500 रुपये की दर से प्रति मानक बोरा का भुगतान आदिवासियों के लिए तो भूमिहीन खेत मजदूरों के लिए दस हजार रुपये की दर से वार्षिक सहायता उनके आर्थिक सशक्तीकरण में सहयोगी बनेगी। रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य योजनाओं का भी अनुपालन होना है।

विधानसभा चुनाव में उम्मीदों भरे वादों और रोष के अंडर करंट का प्रभाव सामने आए दो महीना हो चुका है। अब विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस नेताओं का आमना-सामना होना है। विष्णुदेव के नेतृत्व में दोनों मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव जिस तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं, उससे स्पष्ट है कि सदन में आक्रामकता दिखाने वाले कांग्रेसी विधायकों को उसी के अनुकूल जवाब मिलेगा। सीजीपीएससी भर्ती घोटाले की सीबीआइ जांच की घोषणा के बाद ईडी ने शराब, कोयला परिवहन एवं महादेव एप से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की गति भी बढ़ा दी है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और उनके करीबियों के यहां आयकर छापे की प्रक्रिया जारी है। विपक्ष के समक्ष आक्रामण के अवसर से ज्यादा खुद के बचाव की चुनौती कहीं ज्यादा है। इन सबके बीच सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र में सबसे बड़ी चुनौती वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सामने है। भाजपा की गारंटी को पूरा करने के साथ ही प्रदेश के विकास की योजनाओं को गति देने के लिए बजट प्रबंधन करना आसान नहीं होगा। पूर्व आइएएस अधिकारी चौधरी की परीक्षा नौ फरवरी को होनी है। कर्मचारियों में पनप रहे असंतोष को दूर करना है तो सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को आगे भी बढ़ाना है। उन्हें गारंटी की यात्रा के साथ ही प्रदेश की शिक्षा, चिकित्सा और ढांचागत विकास की यात्रा को सुनिश्चित करना होगा। इन सभी दृष्टिकोण से आने वाला सप्ताह राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या अपनी मौत की फर्जी खबर प्रचारित करने के लिए पूनम पांडे के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए?

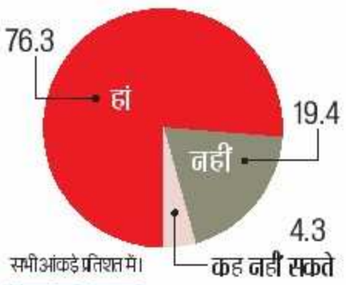

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस मिलकर भाजपा के लिए कड़ी चुनौती प्रस्तुत कर सकेंगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

भग लो मढ़ कर चट्ट से कोई भी आरोप,
राजनीति में वह समय आज हो गया लोप।
आज हो गया लोप ब्रूक या तो दिखलाओ,
अथवा क्राइम ब्रांच जाय हाजिरी बजाओ।
लंबी-लंबी बात करो जनता को ठग लो,
उससे अच्छा आप सियासत छोड़ो भग लो!
- ओमप्रकाश तिवारी

मंथन

बेसहारा गोवंश की समस्या

बेसहारा पशुओं विशेष रूप से गोवंश की अस्मिता कायम रखने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को इस संबंध में एक समर्पित मंत्रालय और राष्ट्रीय गोसेवा नीति बनाए जाने की आवश्यकता है

ईश्वर दास
अध्यक्ष, श्रीकृष्णायन देसी गौरक्षाशाला

भारत में आज लाखों की संख्या में बेसहारा पशु घूम रहे हैं। वर्ष 2019 में बीसवीं पशु धन गणना के बाद भारत सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें 50.21 लाख पशुओं को बेसहारा माना गया है। राजस्थान 12.72 लाख पशुओं के साथ पहले पायदान पर है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में 11.84 लाख पशु बेसहारा हैं। सड़कों से लेकर खेत-खलिहान तक इनका कोई भी पुरसाहाल नहीं है। इनके पेट में प्लास्टिक का कचरा जमा होने की समस्या विकराल होती जा रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार गोसंरक्षण के लिए काम करती प्रतीत होती है। प्रदेश के सभी जिलों में आश्रय स्थल बनाए गए हैं। ग्राम समाज की जमीन पर छोटी गौशालाएं भी बनाई गई हैं। इसके साथ गोपालन करने वाले किसानों को गाय पालने के लिए प्रति गाय 50 रुपये प्रति दिन का प्रविधान किया गया है। तीन गाय पालने वाले किसानों को योजना के तहत 4,500 रुपये मासिक मिलते हैं। सरकार ने गायों के लिए अभयारण्य बनाना शुरू किया है। इन सभी प्रयासों के बावजूद बेसहारा गायों की समस्या विकराल होती जा रही है। गोकशी एवं गौरक्षा समर्थकों की राजनीति के पासे में फंसी बेचारी गाय को और पिसने से कौन व कैसे रोक सकेगा? इस सवाल का जवाब सरकार और समाज को मिल कर ही खोजना होगा।

वस्तुतः संविधान निर्माताओं ने पंथनिरपेक्षता की शर्त का पालन करने हेतु गोवंश के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को मान्यता देने से इन्कार कर दिया। इससे आस्थावान बहुसंख्य समाज आहत हुआ। अयोध्या में श्रीराम की पुनर्स्थापना से जिस नए युग का प्रवर्तन हुआ, इस अन्याय के प्रति समझदारी युक्त प्रयास भी इसी युग में संभव होगा। राम और कृष्ण की भूमि पर गंगा और यमुना जैसी नदियां पवित्रता का प्रतीक रहीं और गोचर भूमि पर गोवंश निर्भीक विचरण करता रहा। मुगलों के शासन काल में गोकशी का संकट शुरू हो गया और अंग्रेजों के काल में यह समस्या विकराल रूप धारण करती है। आजादी के बाद पहली बार 19 नवंबर 1947 को पशुरक्षण और संवर्धन कमिटी बनाई गई। तभी से गोसेवा के नाम पर गौरक्षा का राजनीतिक कार्यक्रम जारी है। फिर श्वेत क्रांति के युग में कत्लखाना तक पहुंचने से चूक गई देशी गाय के लिए नस्ल का संकट खड़ा हो गया। कुदरत से गौवंश को जो कुछ भी मिला, क्या आज इनमें से कुछ भी शेष रह गया?

गोपालक कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के युग में ही नहीं, अपितु आधुनिक भारत में भी जलस्रोत और गोचर भूमि मानवीय बसावट के अभिन्न अंग रहे। 21वीं सदी के आरंभ में ही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार धर्मपाल जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पशु आयोग गठित करती है। हालांकि नौकरशाही के रवैये से क्षुब्ध होकर उन्होंने इस जिम्मेदारी से स्वयं को मुक्त करना ही उचित समझा। इस कड़ी में 19 जुलाई 2002 को लिखी उनकी एक टिप्पणी आयोग की रिपोर्ट में शामिल है। इस संकट के निवारण में कौन और कैसे का सम्यक उत्तर इसमें मिलता है। केंद्र और राज्य की सरकारों को इस पर विचार करना होगा। इसके बिना संकट का निवारण संभव नहीं है।

औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित सरकार के कोप का शिकार होती रही गोवंश के लिए सहकारिता मंत्रालय की तरह विशेष मंत्रालय गठित करना चाहिए। गाय की सुरक्षा और संवर्धन के लिए इसे पशुपालन विभाग से अलग करना उचित रहेगा। गौरक्षा की व्युत्पत्ति के इस दौर में गोसेवा का कार्य सुनिश्चित नहीं हो सका। कम से कम सौ दिनों के रोजगार वाली मनरेगा योजना को आज गोसेवकों तक पहुंचाने से स्थिति बदल सकती है। आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करने वाली सरकार इसे शीघ्र ही लागू कर सफलता अर्जित करे। गोसंरक्षण और संवर्धन के केंद्रीय कानून और राज्य कानूनों में अनेक प्रकार के भ्रम और अस्पष्टता की स्थिति बनी हुई है। इसलिए स्पष्ट राष्ट्रीय गोसेवा नीति बनाने की भी जरूरत है। इस समस्या के निवारण हेतु एक सक्षम राष्ट्रीय आयोग गठित करना कारगर होगा। केंद्र और राज्यों में सक्रिय गोसेवा आयोग भी इस काम को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं।

बेसहारा गायों के विकराल होते संकट को दूर करने के लिए गोसरंक्षण अभ्यारण्य को आज गोचर के तौर पर परिभाषित करने की आवश्यकता है। नदी किनारे की जमीन (खादर) ही सही मायनों में गोवंश का प्राकृतिक आवास रहा है। रामराज्य का आधार इन मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता की मांग करती रहेगी। इन सभी सूत्रों को साधने के लिए केंद्रीय पशुपालन मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राष्ट्रीय गोसेवा नीति पर विचार करने की आवश्यकता है।

बेसहारा गायों की समस्याओं का समाज एवं सरकार को मिलकर करना होगा समाधान। फाइल

****